इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन)
वर्ष 2019-20 के लिए निष्पादन/गतिविधियों पर वार्षिक समीक्षा

पृष्ठभूमि

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन), रेल मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम (सीपीएसई) है। यह एकीकृत इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है, जिसे रेलवे, राजमार्ग, पुल, फ्लाईओवर, सुरंग, विमान अनुरक्षण हैंगर, रनवे, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) सब-स्टेशन, विद्युत और यांत्रिकी कार्य, वाणिज्यिक और आवासीय परिसंपत्तियों, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, और अन्य अवसंरचनात्मक गतिविधियों सहित प्रमुख आधारभूत अवसंरचना क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है। कंपनी एक अनुसूची 'क', और मिनीरत्न-श्रेणी-I की सार्वजनिक क्षेत्र की सूचीबद्ध कंपनी है।

अब तक, इरकॉन ने विश्वभर के 25 देशों में 128 से अधिक परियोजनाओं और भारत में 390 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया है। यूएसए के इंजीनियरिंग न्यू रिकॉर्ड (ईएनआर) के 2020 संस्करण के अनुसार, इरकॉन भारत का एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम है, जिसने शीर्ष 250 अंतर्राष्ट्रीय संविदाकारों की सूची में स्थान प्राप्त किया है।

वित्तीय विशिष्टताएं

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने स्टैंडएलोन आधार पर 5,442 करोड़ की अब बक की सार्वधिक कुल आय और 5,202 करोड रूपए का प्रचालनिक टर्नओवर प्राप्त किया है।

वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के वित्तीय निष्पादन के कुछ महत्वपूर्ण संकेतक निम्नानुसार हैं:

क्र.सं	विवरण	2019-20 (रू.करोड में)	2018-19 (रू.करोड में)	वृद्धि/(कमी) [% में]
1.	कुल आय/टर्नओवर	5,442	4,680	16%
2.	कुल प्रचालनिक आय /टर्नओवर	5,202	4,415	18%
3.	विदेशी परियोजनाओं से प्रचालनिक आय	443	586	(24)%
4.	भारतीय परियोजनाओं से प्रचालनिक आय	4,759	3,829	24%
5.	कर पूर्व लाभ	673	615	9%
6.	कर पश्चात लाभ	490	445	10%
7.	कुल मूल्य	4,161	3,950	5%
8.	लाभांश	223.38*	202.63	10.24%

* इसमें प्रस्तावित लाभांश (आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अध्याधीन) शामिल है।

कंपनी ने फरवरी, 2020 में 126.50 करोड रूपए (लगभग) की राशि के प्रति शेयर 13.45 रूपए (प्रति 10 रूपए के फेस मूल्य पर) के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है और वार्षिक आम बैठक में 96.87 करोड रूपए की राशि के प्रति शेयर 2.06 (प्रति 2 रूपए के फेस मूल्य पर) के अंतिम लाभांश की घोषणा की है। इस प्रकार, वर्ष 2019-20 के लिए घोषित कुल लाभांश (लाभांश संवितरण कर सहित) 223.38 करोड़ रुपये परिकलित किया गया है, जो 94.05 करोड रूपए की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 237.50 प्रतिशत है और दिनांक 31 मार्च 2020 को कर पश्चात लाभ का 45.60 प्रतिशत तथा निवल परिसिंपत्ति का 5.37 प्रतिशत है।

शेयर पूंजी और सूचीकरण

वर्ष 2019-20 के दौरान, प्रति 10 रूपए की फेस मूल्य के एक (1) इक्विटी शेयर को प्रति 2 रूपए के फेस मूल्य के पांच (5) इक्विटी शेयरों में विभाजित करने के लिए कंपनी के सदस्यों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की है और इसके परिणमस्वरूप, कंपनी के सहयोग ज्ञापन में पूंजी खंड में संशोधन किया गया है। शेयर के फेस मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव स्टॉक एक्सचेंजों

दिनांक 30 अप्रैल 2020 को दिखा जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध (बीएसई और एनएसई) हैं और दिनांक 08 अप्रैल 2020 को प्रत्येक दो रूपए के फेस मूल्य के शेयरों की निगमित क्रेडिट कार्रवाई को पूरा कर लिया गया है क्योंकि इस प्रयोजन हेतु रिकार्ड तिथि 07 अप्रैल 2020 है। तदनुसार, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी परिवर्तित होकर 400 करोड़ रूपए हो गई है, जिसमें प्रति 2 रूपए के 200 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर शामिल हैं और कंपनी की जारी और प्रदत्त शेयर पूँजी 94.05 करोड़ रूपए है, जिसमें प्रति 2 रूपए के 470,257,870 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 10.53% भाग का आरंभिक पब्लिक ऑफर (आईपीओ) के माध्यम से विनिवेश किया था। भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 89.18% भाग है। इसके अतिरिक्त, 'सूचीकरण विनियम' के अनुसार, चूंकि इरकॉन एक सूचीबद्ध निकाय है, इसलिए उसे प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियम, 1957 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) के नियम 19(2) और नियम 19क की अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक है। सेबी ने एमपीएस अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए अगस्त, 2021 तक अनुमति प्रदान की है। इसलिए, 25% के एमपीएस के अनुपालन के लिए, भारत सरकार (जीओआई) को भावी पब्लिक ऑफर (एफपीओ) के माध्यम से अपनी शेयरधारिता का कम से कम 14.18% तक विनिवेश करने की आवश्यकता है।

दिनांक 31 मार्च, 2020 को इरकॉन को बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से भारत की शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में शामिल किया गया है, जिसका बाजार पूंजीकरण 3,584 करोड़ रूपए है।

कोविड-19 का प्रभाव

कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत और दिनांक 24 मार्च, 2020 से भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसलिए, कंपनी का प्रचालन भी प्रभावित हुआ है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, कंपनी ने केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी लॉकडाउन दिशानिर्देशों के अनुपालन में सभी चालू परियोजनाओं में अस्थायी रूप से प्रचालनों को बंद कर दिया था। इन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन

प्रतिबंधों के कारण कंपनी के सामान्य प्रचालनों पर प्रभाव पड़ा और लॉकडाउन के दौरान परियोजना निष्पादन में अवरोध उत्पन्न हुआ और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा उत्पन्न हुई तथा कार्मिकों की अनुपलब्धता बनी रही। अब अधिकतर परियोजनाओं में निर्माण कार्य आरंभ हो गए हैं। कंपनी व्यावसायिक चुनौतियों के प्रभाव को कम करना के लिए हरसंभव उपायों कर रही है। हालांकि, कंपनी की दीर्घकालिक दिशात्मक प्राथमिकताएं यथावत हैं। कोविड-19 के आलोक में और प्रचालनिक वातावरण पर इसके संभावित प्रभावों के दृष्टिगत, कंपनी की प्रमुख प्राथमिकताएं, आपूर्ति श्रृंखला की गहन निगरानी करना, नकदी का संरक्षण करना और नियत लागतों को नियंत्रित करना है, और साथ ही विकास क्षेत्रों में निवेश को जारी रखना है।

सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के लिए घर से कार्य (वर्क फ्रॉम होम) और कर्मचारियों के लिए रोस्टर के माध्यम से कंपनी की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, तीव्रता के साथ कार्य हेतु अधिकारियों में ई-ऑफिस प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) को बनाए रखने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कार्यस्थल पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) निर्धारित की हैं।

परियोजनाओं पर कार्य आरंभ होने के साथ, कंपनी निरंतर अपने प्रचालनों की समीक्षा कर रही है और महामारी के कारण समय की हानि को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रही है।

प्रचालनिक विशेषताएं

विदेशी परियोजनाएं

बांग्लादेश, अल्जीरिया और श्रीलंका में **तीन चालू विदेशी परियोजनाएं** निम्नलिखित हैं:

(क) <u>बांग्लादेश</u>- बांग्लादेश रेलवे के लिए खुल्ना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत तटबंध का निर्माण, ट्रैक, सभी सिविल कार्य, प्रमुख और छोटे पुल (रूपा पुल को छोड़कर) का निर्माण और डब्ल्यूडी-1 के प्रति ईएमपी का क्रियान्वयन कार्य।

(ख) <u>अल्जीरिया-</u> एएनईएसआरईएफ, परिवहन मंत्रालय, अल्जीरिया द्वारा प्रदान की गई अल्जीरिया में दोहरी रेलपथ लाइन (93 किलोमीटर) की स्थापना।

(ग) <u>श्रीलंका</u> - परिवहन और नागर विमानन मंत्रालय, श्रीलंका सरकार के अधीन श्रीलंकन रेलवे द्वारा प्रदान की गई भारतीय ऋण तर्ज पर महो से ओमानथई तक रेलवे लाई का स्तरोन्नयन, रेलपथ पुनर्वासन और अनुषंगी कार्य।

वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने **श्रीलंका में एक परियोजना** प्राप्त की है, जिसमें भारतीय ऋण तर्ज पर महो से ओमानथई तक रेलवे लाई का स्तरोन्नयन, रेलपथ पुनर्वासन और अनुषंगी कार्य शामिल है। इस परियोजना लगभग 637.22 करोड़ रुपये के मूल्य पर श्रीलंका सरकार के परिवहन और नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत श्रीलंकन रेलवे द्वारा प्रदान की गई है।

घरेलू परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, इरकॉन ने **भारत में तीन घरेलू परियोजनाओं** को पूरा किया है, यथा:

(क) रेल मंत्रालय के लिए 2,605 करोड रूपए के मूल्य पर अतिरिक्त कार्यों सहित रायबरेली में नए रेल डिब्बा कारखाने की स्थापना।

(ख) रेल मंत्रालय, बिहार सरकार के लिए 671 करोड़ रुपये के मूल्य पर बिहार राज्य में सड़क उपरिपुल (आरओबी) का निर्माण।

(ग) रेल मंत्रालय, राजस्थान सरकार के लिए 649 करोड़ रूपए के मूल्य पर राजस्थान राज्य में सड़क उपरिपुल (आरओबी) का निर्माण।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त, इरकॉन **99 साल के लिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, बांद्रा पूर्व, मुंबई में 4.3 हेक्टेयर रेलवे भूमि का वाणिज्यिक विकास** भी कर रहा है। इसके लिए, इरकॉन ने उक्त भूमि खंड पर वाणिज्यिक विकास के लिए इरकॉन को पटद्यटाधारक अधिकार हस्तांतरित करने के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के साथ दिनांक 26 मार्च, 2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसकी भूमिका और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, इरकॉन आरएलडीए से अपफ्रंट पट्टा प्रीमियम के कुल 3 प्रतिशत की समतुल्य राशि हेतु

शुल्क प्राप्त करने के लिए पात्र है, जिसके लिए इरकॉन, आरडीएडीए और भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) के बीच एक त्रिपक्षीय ऋण समझौता हुआ था।

निगमित योजना के संदर्भ में, इरकॉन ने इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, चयनित विविधीकरण के लिए **रियल एस्टेट सेक्टर** की पहचान की है। नोएडा और गुड़गांव में स्थित कंपनी की संपत्तियों और देशभर में फैली कंपनी की अन्य अचल परिसंपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने अपने रियल एस्टेट व्यवसाय की व्यवस्था के लिए एक अलग सम्पदा प्रबंधन विभाग की स्थापना की है।

आर्डर बुक

वर्ष 2019-20 के दौरान, इरकॉन ने 633.48 करोड रूपए मूल्य के कार्य प्राप्त किए हैं। दिनांक 31 मार्च 2020 तक ऑर्डर बुक मूल्य 30,713 करोड रूपए (लगभग) है, जबकि दिनांक 31 मार्च 2019 को यह 33,901 करोड रूपए (लगभग) था।

समझौता ज्ञापन (एमओयू) रेटिंग / पुरस्कार

रेलवे मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित वर्ष 2018-19 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत कंपनी की रेटिंग 'उत्कृष्ट' है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 7वां फिक्की उद्योग हेतु गुणवत्ता प्रणाली उत्कृष्ट पुरस्कार, ईटी नाउ: स्टार्स ऑफ़ द इंडस्ट्री पुरस्कार, 16वां आईसीएमएआई लागत प्रबंधन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता, दो क्षेत्रों यथा जोखिम प्रबंधन और शिवपुरी गुना हाईवे परियोजना हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ईटी नाउ: वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस अवार्ड, 7वां पीएसयू गवर्नेंस नाउ अवार्ड, विभिन्न श्रेणियों के लिए एसकेओएचसी ऑर्डर ऑफ मेरिटफोर।

सीएसआर और संधारणीयता

वित्तीय वर्ष 2020 के लिए सीएसआर बजट 9.88 करोड़ रूपए था, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी द्वारा अपनी भारतीय परियोजनाओं से प्राप्त औसत शुद्ध लाभ का 2% है। वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान, इरकॉन ने अपनी सीएसआर गतिविधियों पर 10.04 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, और 5.38 करोड़ के शेष बजट के प्रति प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और राहत आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम केयर्स निधि) में 4.5 करोड़ रूपए की कुल निधि का दान किया है। वर्ष 2019-20 की समाप्ति के पश्चात, इरकॉन ने पीएम केयर्स निधि में 15.50 करोड रूपए की अतिरिक्त राशि का अंशदान किया है।